साप्ताहिक

डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21

RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 28 जून 2021, वर्ष-7, अंक-13

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

- मप्र में घटे अन्नदाता और बढ़ गए खेतिहर मजदूर
- किसानी से जुड़े 90 फीसदी परिवार इसी तबके के हैं
- भारत में करीब 86 फीसदी छोटे और सीमांत किसान
- दिनों-दिन खेती-किसानी की चुनौतियां बदलती जा रहीं
- तमाम विषम परिस्थिति के बावजूद किसान हो रहे मालामाल

स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट में खुलासा

शिवराज में किसान खुशहाल

अरविंद मिश्र, भोपाल

करीब 15 साल पहले कृषि के क्षेत्र में सबसे पिछड़े राज्य के रूप में गिना जाने वाला मप्र आज देश का सबसे बड़ा अनाज उत्पादक राज्य बना हुआ है।

हालांकि स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021 की रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि देश के अन्य राज्यों की तरह प्रदेश में भी किसानों की संख्या घट रही है। लेकिन इसके बावजूद एमपी के किसान सबसे खुशहाल हैं। इसकी वजह यह है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनकी नीतियां

किसान हितैषी हैं। वे खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए कृत-संकल्पित होकर किसानों को विभिन्न योजनाओं में लाभांवित कर रहे हैं। प्रदेश को राष्ट्रीय-स्तर पर दिया जाने वाला कृषि कर्मण अवार्ड लगातार सातवीं बार प्राप्त हुआ है। वहीं मप्र में किसान लगातार कम हो रहे हैं, जबकि कृषि श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों के अनुसार मप्र में कृषि क्षेत्र में करीब 31.6 मिलियन लोग कार्यरत हैं। जिनमें 22 मिलियन किसान हैं। कृषि कार्य में जहां 45 फीसदी किसान लगे हुए हैं,वहीं 55 फीसदी कृषि श्रमिक हैं। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021 की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि मप्र सहित देशभर में किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है।

राज्यवार प्रतिशत में किसान, कृषि श्रमिक

उप्र	49	51
महाराष्ट्र	48	52
आंध्रप्रदेश	28	72
प बंगाल	33	67
बिहार	28	72
तमिलनाडु	31	69
एमपी	45	55
राजस्थान	73	27
कर्नाटक	48	52
गुजरात	44	56
ओडिशा	38	62
छत्तीसगढ़	44	56
पंजाब	55	45

मुख्यमंत्री शिवराज के सशक्त और चमत्कारिक नेतृत्व में सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय ने उन्हें खुशहाल बनाया है। सरकार ने कोरोना की पहली लहर की विपत्ति के बाद भी रिकॉर्ड गेहूं का उपार्जन कर पंजाब को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया। किसान ज्यादा से ज्यादा संख्या में बीमा कराएं, इसके लिए सरकार ने प्रेरित किया था।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

कोरोना में खेती बनी सहारा

मध्यप्रदेश में कोरोना महामारी के बीच गेहूं और धान का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। यही नहीं लॉकडाउन के बाद गांव लौटे लोगों को रोजगार देने में कृषि बड़ा संबल बनी। एक ओर जहां कृषि क्षेत्र को इस अभूतपूर्व प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा। वहीं संक्रमण की लहर के बीच मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबल देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। वहीं मप्र का किसान इस दौर में भी खुशहाल है।

फसलों के नुकसान की भरपाई

मप्र में सरकार फसलों के नुकसान की भरपाई हर हाल में करती है। पिछले साल अतिवृष्टि से खराब खरीफ फसलों का बीमा किसानों को पांच हजार करोड़ मिल सकता है। इसके लिए फसलों को हुए नुकसान का आकलन कराकर बीमा दावों को तैयार किया जा रहा है। प्रक्रिया पूरी करके बीमा की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा कराई जाएगी। प्रदेश में पिछले साल 44 लाख से ज्यादा किसानों ने खरीफ फसल का बीमा कराया था।

फिर भी श्रमिकों का टोटा

मप्र सहित देशभर में किसानों की संख्या घट रही है और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, उसके बाद भी कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का टोटा बना हुआ है। कोरोना आपदा के दौरान बीते एक साल में दो बार शहरों से मजदूरों के वापस गांवों को लौटने के हालात बन गए। इसके बावजूद गांवों में फसलों के कटाई जैसे तमाम खेती-किसानी के काम के लिए मजदूर नहीं मिल रहे या उनकी कमी है। खेतिहर मजदूरों की संख्या और उनका शहरों तथा अन्य पेशों की ओर पलायन भी बढ़ा है।

जैविक खेती पर फोकस

मप्र के किसानों को अब फूड प्रोसेसिंग से भी जोड़ा जा रहा है, जिससे उनके द्वारा उत्पादित कच्चे माल का उपयोग फूड प्रोसेसिंग में कर रोजगार भी बढ़ाए जाएंगे। जैविक खेती को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले की उद्यानिकी फसल को पहचान दिलाने की कोशिशें भी प्रांरभ की गई हैं। किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए सहकारी बैंक का भरोसा बेहद जरूरी है। इस दिशा में मुख्यमंत्री ने 1500 करोड़ रुपए भरने का ऐलान कर दिया है।

दावाः देश में औषधीय शराब बनाने वाली जीवाजी पहली यूनिवर्सिटी

मप्र में 'औषधीय शराब' बढ़ाएगी इम्युनिटी

संवाददाता, ग्वालियर

जीवाजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च सेंटर में शिक्षक तथा दो रिसर्च स्कॉलर्स ने फलों और उनके पेड़ की पत्तियों से 10 प्रकार की औषधीय शराब बनाई है। दावा है कि यह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और इससे डायबिटीज व कॉलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो सकता है। इम्युनिटी लेवल भी बढ़ेगा। औषधीय शराब में 8 से 14 प्रतिशत तक एल्कोहल होता है। दावा है कि इतने तरह की शराब देश की किसी भी यूनिवर्सिटी की लैब में तैयार नहीं की गई है। आम के पत्तों की शराब का पेटेंट कराया जा रहा है। अन्य शराब के लिए आयुर्वेदिक दवा कंपनी तथा पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनियों से बात चल रही है।

ऐसे बनाई शराब

पत्तों या फलों को साफ पानी से धोकर पानी में डाल देते हैं फिर उस को पीसकर उसमें गुड़ एवं यीस्ट मिलाकर 15 दिन के लिए रख दिया जाता है। उसके पश्चात फिल्टर करके 4 डिग्री तापमान पर स्टोर किया जाता है। यह रिसर्च प्रो. जीबीकेएस प्रसाद तथा उनकी दो रिसर्च स्कॉलर रुपाली दत्त और ललिता कुशवाह द्वारा की गई है।

फलों के पत्तों से बनी शराब के गुण

पपीते के पत्ते की शराबः पत्ते में पापाइन, कीयो पापाइन, कोमेरिन तत्व व एंटी डायबिटिक गुण होते हैं।

जैतून के पत्ते की शराबः ऑलियारायिन, कैफिक एसिड जैसे तत्व एंटी डायबिटिक गुण रखते हैं।

सीताफल के पत्ते की शराबः एसिटोजेनिन, रियूटिन जैसे तत्व इसे सेहत के लिए अच्छा बनाते हैं।

अमरूद के पत्ते की शराबः एविनोइड, अल्फा केडिनॉल, नेरिन जेनिन तत्व होते हैं। यह डायबिटीज कम करती है।

आम के पत्ते की शराबः इसमें मैग्नीफेरिन, बेंजोफिनॉल, जैंथोन जैसे बायोएक्टिव तत्व होते हैं जो शुगर व कैंसर की रोकथाम करते हैं।

आंवलाः गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड तत्व इम्युनिटी बढ़ाते हैं।

बेलः मार्मिलोसिन, कोमेरिन आदि तत्व पाचन शक्ति ठीक कर शुगर को नियंत्रित करते हैं।

जामुनः इसमें मौजूद तत्व शुगर को नियंत्रित करते हैं।

सेवःहाइड्रोसिनेमिक एसिड, केटेकिन जैसे तत्व हृदय से जुड़ी बीमारियों को कम करते हैं।

इनका कहना है

चूहों पर फल व पत्तों की शराब का उपयोग करने के बाद यह पाया गया है कि यह रक्त शर्करा को कम कर कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करती है। औषधीय शराब में एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी इनफ्लेमेट्री गुण पाए जाते हैं।

प्रो. जीबीकेएस प्रसाद, शोधकर्ता, जीवाजी विवि ग्वालियर

गुजरात की श्रीराम कंपनी के नाम से हो रही थी पैकिंग

जबलपुर में नकली खाद की फैक्टरी का भंडाफोड़

115 बोरी में पांच हजार 750 किलो नकली खाद जब्त

संवाददाता, जबलपुर

जबलपुर में अब नकली खाद की फैक्टरी का भंडाफोड़ हुआ है। मझौली क्षेत्र स्थित एक फार्म हाउस में ये फैक्टरी संचालित थी। यहां गुजरात की कंपनी के नाम पर 5-5 किलो खाद के पैकेट तैयार किए जा रहे थे। मौके से 115 बोरी नकली खाद और पांच किलो के खाली रैपर जब्त किए गए हैं। पैकेट के अंदर चूने जैसा पाउडर मिला है। सैंपल की जांच कराई जा रही है। सिहोरा एसडीएम को सूचना मिली थी कि गौरहा भिटौनी स्थित हेलन डिसूजा के फार्म हाउस में नकली खाद बनाकर पैकिंग की जा रही है। तैयार माल को यहां से शिफ्ट किया जाना है। इस सूचना पर वे पुलिस, एसडीओ कृषि मनीषा पटेल, नायब तहसीलदार रूबी खान और नायब तहसीलदार के साथ मौके पर दबिश दी।

मौके पर मिले खाली रैपर

फार्म हाउस में बने कमरे को सील कर दिया है। मौके से टीम ने बड़ोदरा गुजरात की उत्तम श्रीराम क्रॉप साल्यूशन कंपनी के 5-5 किलो के भरे और खाली पैकेट भी जब्त किए। कृषि विभाग की ओर से फार्म हाउस मालिक जेसन डिसूजा मास्टरमाइंट विद्याचरण लोधी सहित तीन के खिलाफ मझौली थाने में नकली खाद बनाने का प्रकरण दर्ज कराया गया है। तीसरा आरोपी ग्वालियर में होने की वजह से गिरफ्तार नहीं हो पाया है।

सफेद पाउडर को पैक कर रहे थेः प्रशासन ने पांच-पांच किलो के खाली और पैक पैकिट जब्त किए हैं, उस पर जिंक सल्फर लिखा है। दोनों का अनुपात 33:15 का दर्शाया गया है। हर पैकेट पर कीमत 650 रुपए दर्शाया गया था।

इनका कहना है

बोरिया में चूने जैसा पाउडर मिला है। यह चूना है या इसमें कुछ और मिलावट है, इसकी जांच के लिए कृषि विभाग ने सैंपल लिए हैं। आरोपी कोई लाइसेंस या अन्य दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। आरोपी रात में इस खाद को यहां से हटाने वाले थे। फार्म हाउस का कमरा सील कर दिया गया है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है।

आशीष पांडे, एसडीएम, सिहोरा

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा

कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश कर रहा लगातार प्रगति

संवाददाता, भोपाल

केन्द्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कृषि के क्षेत्र में विगत 15 वर्षों से बेहतरीन कार्य कर रही है। किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने भारत सरकार द्वारा भोपाल में नेफेड का क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे निश्चित ही किसानों को लाभ मिलेगा।

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय बीज निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल के भवन एवं तीन हजार एमटी क्षमता के बीज गोदाम तथा नेफेड के भोपाल कार्यालय का वर्चुअल शुभारंभ किया। इस दौरान तोमर ने कहा कि मप्र कृषि प्रधान राज्य है, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं कृषि मंत्री कमल पटेल दोनों खेती-किसानी से जुड़े हैं। दोनों ही किसानों को उनकी उपज के वाजिब दाम दिलाने तथा कृषि क्षेत्र को समृद्ध करने के लिए बहुत अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तोमर ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार को भारत सरकार की ओर से पहले भी पूरा सहयोग किया गया है और आगे भी पूरी मदद की जाती रहेगी। किसानों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कृत-संकल्पित है और किसानों की मदद करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी।

- नेफेड का एमपी के किसानों को मिलेगा लाभ
- भोपाल में नेफेड के क्षेत्रीय कार्यालय का श्रीगणेश

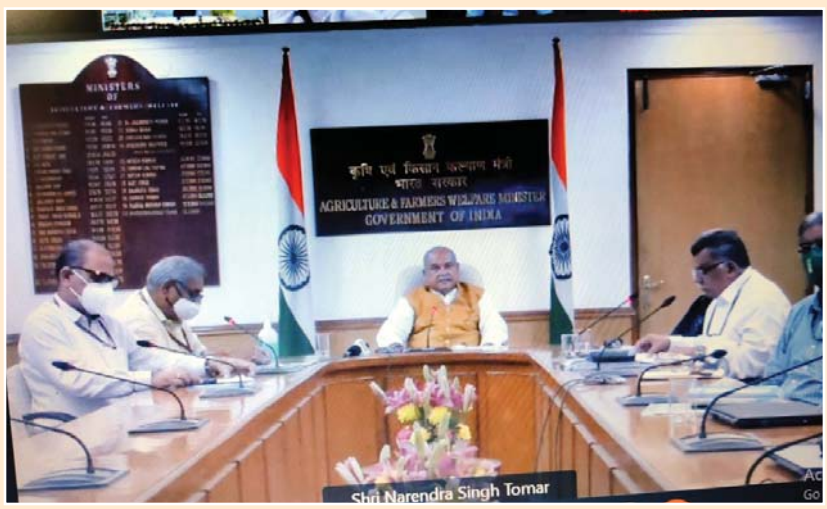

परिवर्तन का संकल्प पूरा

वहीं मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को पूरा करके दिखाया है। राज्य में समर्थन मूल्य पर किसानों की उपज के क्रय से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और केन्द्रीय कृषि मंत्री का प्रदेश को आवश्यकता अनुसार समय-समय पर खाद्य की निरंतर आपूर्ति करने, ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने के लिए आभार व्यक्त किया।

तीन लाख किसान पीएम और सीएम 'सम्मान' के पात्र नहीं

भोपाल। प्रदेश में 1 फरवरी 2019 के बाद जिन किसानों ने जमीनें खरीदी हैं, वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पाने के पात्र नहीं हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि में जिन किसानों के नाम हैं, वे ही मुख्यमंत्री किसान सम्माननिधि के पात्र हैं। इस तरह पिछले 29 महीनों में जिन किसानों ने जमीनें खरीदी हैं, उन्हें इन दोनों योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे किसानों की संख्या 3 लाख के करीब है। नई गाइडलाइन 2024 में जारी होगी, तब नए किसानों के नाम जोड़े जाएंगे, यानी 1 फरवरी 2019 से 2024 के बीच 10 लाख किसान दोनों योजनाओं का लाभ नहीं पा सकेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि की पात्रता में 1 फरवरी 2019 की स्थिति में ही जिन किसानों के नाम जमीन है, वे ही इस योजना में लाभ लेने के पात्र हैं। इसके तहत हर साल 3 किस्तों में 2-2 हजार रुपए कुल 6 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं। इसी तरह राज्य सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्माननिधि के तहत किसानों को चार हजार रुपए का भुगतान दो किस्तों में किया जाता है। इस तरह केंद्र व राज्य की राशि मिलाकर 10 हजार रुपए किसानों के खाते में डाले जाते हैं। दोनों योजनाओं का 77 लाख किसानों को फायदा मिलता है।

नई गाइडलाइन जारी होने के बाद जोड़े जाएंगे नाम

इनका कहना है

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसान सम्माननिधि का फायदा ज्यादा से ज्यादा किसानों को मिल रहा है। जो छूट रहे हैं, उनके नाम भी तय प्रक्रिया के हिसाब से जोड़े जाएंगे।

कमल पटेल, कृषि मंत्री

अब किसानों को सिंचाई के लिए नहीं खलेगी पानी की कमी

- ग्वालियर के आठ तालाबों का 627 लाख से संवारेगी सरकार
- राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत के प्रयासों से जारी हुए आदेश

संवाददाता, भोपाल

ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 8 तालाबों का 627 लाख 57 हजार की लागत से जीर्णोद्धार कार्य के प्रशासकीय आदेश जारी कर दिए गए है। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह के विशेष प्रयास से प्रशासकीय स्वीकृति जारी हुई है। मंत्री ने बताया कि आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के तहत राज्य सरकार विकास कार्यों पर पूरा पूरा ध्यान दे रही है।

कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में विकास कार्यों और किसानों की योजनाओं को गति प्रदान करना राज्य शासन की प्राथमिकता है। ग्वालियर ग्रामीण क्षेत्र में भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों को गहरा करना, उनके जीर्णोद्धार के कार्यों को प्राथमिकता से कराने के लिए उनके द्वारा पिछले एक दशक से लगातार पहल की जा रही थी, जिसे अब सफलता प्राप्त हुई। इन तालाबों के रिनोवेशन होने से तालाबों के आसपास के हजारों किसानों को, ग्रामीणों को पीने के लिए पानी, मवेशी के लिए पानी और खेती के लिए पानी मिलेगा। इससे ग्रामीणों के जीवन में बदलाव आएगा। मंत्री ने कहा कि वर्तमान में आवश्यकता है कि भू-जल संरक्षण के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि भविष्य में हमें जल संकट की चुनौती का सामना नहीं करना पड़े। इसके लिए हमें आज से प्रयास करना होगा और इसी कड़ी में तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाना है।

इन तालाबों पर खर्च होंगे लाखों

जिन तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है इनमें 13 लाख 18 हजार से बहांगी खुर्द तालाब, 15 लाख से बड़ेरा तालाब, 19 लाख 27 हजार से टिहौली तालाब, 50 लाख 20 हजार से बिजौटी तालाब, 25 लाख 30 हजार से जखारा तालाब, 111 लाख 50 हजार से बिलारा तालाब, 165 लाख से पारसेन तालाब और 232 लाख 12 हजार से जलालपुर पिकअप बियर शामिल है।

किसानों से धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

मंत्री ने व्यापारी से वसूल कर किसानों को दिलाई राशि

संवाददाता, भोपाल

किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने सनावद में किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी से राशि वसूल कर किसानों को दिलवाई। उन्होंने 25 से अधिक किसानों को 50 लाख रुपए से अधिक की राशि वापस करवाई। मंत्री ने कहा है कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उनसे पाई-पाई वसूल की जाएगी। मंत्री ने बताया कि कृषि उपज मंडी, सनावद में अथर्व इंटरप्राइजेस ने 192 कृषकों से धोखाधड़ी कर लगभग तीन करोड़ 17 लाख 70 हजार रुपए मूल्य का 3500 क्विंटल डॉलर चना खरीदा और भुगतान नहीं किया। कृषि मंत्री के संज्ञान में उक्त धोखाधड़ी का प्रकरण आने पर तत्काल संयुक्त संचालक, मंडी बोर्ड, इंदौर चन्द्रशेखर वशिष्ठ को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजते हुए व्यापारी के माल की जब्ती कराई। मां रेवा कोल्ड स्टोरेज तथा बुलढाना बैंक वेयर-हाउस से जप्त किए गए 7,100 क्विंटल डॉलर चना और अन्य उपज की लागत लगभग सात करोड़ रुपए आंकी गई है। मंत्री ने डिफाल्टर व्यापारी की जब्त सामग्री से 18 जून को 50 किसानों को 50 लाख रुपए से अधिक की राशि का ऑनलाइन भुगतान कराया है। उन्होंने किसानों को वर्चुअल संबोधित करते हुए कहा है कि शेष कृषकों के दावों का सत्यापन कर शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा।

जिले के सब्जी विक्रेताओं ने किया गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का सम्मान

दतिया में बनेगी सर्व-सुविधायुक्त सब्जी मंडी

संवाददाता, भोपाल

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दतिया में 50 लाख रुपए की लागत से सर्व-सुविधायुक्त आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण कराया जाएगा। डॉ. मिश्रा सब्जी विक्रेताओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सब्जी मंडी का आधुनिकीकरण किया जाकर विक्रेताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। गृह मंत्री ने सब्जी विक्रेताओं का सम्मान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दतिया की सब्जी मंडी को 50 लाख रुपए की लागत से आधुनिक सब्जी मंडी के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बहु-मंजिला सब्जी मंडी डिजाइन की जाए। सब्जी मंडी में नवीन चबूतरों के साथ बिजली, शीतल पेयजल और शेड के निर्माण भी किए जाएंगे।

भोपाल निगम ने 70 जगहों पर टेट्रा पैक कलेक्शन बॉक्स रखा

दूध, लस्सी, जूस के इस्तेमाल पैकेट से बनेगी कॉपी-किताब

देहरादून में होगी इस कचरे की रीसाइकलिंग

पहले यह किया जा चुका नवाचार

- नगर निगम ने इससे पहले अनुपयोगी दवाओं के कलेक्शन के लिए बॉक्स लगाए थे। इस प्रयास को अच्छा जनसहयोग मिलने पर शहर के कई जरूरमंदों तक जमा की गई दवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
- शहर के 80 से ज्यादा कालोनियों में घरों से निकलने वाली पुरानी कापी-किताबों को एकत्र करने का काम भी निगम द्वारा किया जा रहा है। जिन्हें रीसाइकल करवाकर नई कापियां तैयार करवाई जा रही हैं। जो जरूरमंदों को निः शुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी।

इनका कहना है

नगर निगम द्वारा टेट्रा पैक कलेक्शन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके लिए एक निजी संस्था के साथ करार किया गया है। शहर के 70 जगहों पर बॉक्स लगाकर इन्हें एकत्र किया जाएगा।

एमपी सिंह, अपर आयुक्त, नगर निगम भोपाल

संवाददाता, भोपाल

भोपाल नगर निगम द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत कई तरह के नवाचार किए जा रहे हैं। इन नवाचारों के क्रम में अब निगम कचरे में फेंके जाने वाले टेट्रा पैकेट (मोटे कागज के पैकेट) से कापियां बनवाने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पर दूध, लस्सी और जूस के जो टेट्रा पैक आमलोग कचरे में फेंक देते हैं उन्हें कचरे से छंटवाकर अब निगम उससे कापियां बनवाएगा।

शहर में हर दिन दो टन तक कचरा निकलता है। इसमें से टेट्रा पैक अब तक कचरे के साथ ही खंती तक पहुंचता था, लेकिन यह एक विशेष तरह की पैकिंग होती है जिसे रीसाइकल कर कई उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं, जिनमें कागज भी शामिल है। नगर निगम ने दावा किया है कि मप्र में पहली बार इस तरह का प्रयोग हो रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में पहले से इस तरह की पहल हो रही है। पर्यावरण स्वच्छता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके लिए निगम द्वारा शहर के प्रमुख बाजार, सार्वजनिक स्थान, पार्क, कॉलोनियों में इसके लिए अलग बॉक्स भी रखे जाएंगे।

यह होगा फायदा

कागज निर्माण में कम से कम पेड़ों की कटाई व कचरे से होने वाले प्रदूषण से वातावरण को मुक्त रखने के लिए पेय पदार्थों के खाली पैकेट को रीसाइकल कर कापी, किताब, टेबिल, चेयर आदि उपयोग वस्तुएं बनाई जाएंगी। इसके लिए नगर निगम ने निजी कंपनी द कबाड़ी वाला के साथ मिलकर यह अभियान शुरू किया है। इस अभियान से जुड़ने के लिए नागरिक 7697260260 पर संपर्क भी कर सकते हैं।

70 जगहों पर कलेक्शन बॉक्स

अभियान के तहत शहर को ग्रीन और क्लीन बनाने की दिशा में टेट्रा पैक की तरह दिखने वाले ही बॉक्स लगाए जा रहे हैं। नगर निगम द्वारा निजी संस्थान की मदद से शहर में 70 जगहों पर यह बाक्स लगाए जा रहे हैं। एकत्र होने वाले पैकेट को देहरादून भेजा जाएगा। जहां इसे रीसाइकल किया जाएगा। निगम के पास अब तक तीन टन टेट्रा पैक एकित्रत हो चुके हैं। 10 टन एकित्रत होने के बाद इन्हें रीसाइकल के लिए भेजा जाएगा।

एक जुलाई से अब महंगी होगी जमीन की रजिस्ट्री

संवाददाता, भोपाल

कोरोना की दूसरी लहर का कोप खत्म होने के बाद अब आम आदमी पर कई तरह के भार पड़ने वाले हैं। इनमें से एक है रजिस्ट्री का भार। यदि आप नई संपत्ति खरीद रहे हैं तो 30 जून तक उसकी रजिस्ट्री करा लें। वरना 1 जुलाई से नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू की जाती है तो जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे। अगर आप मकान, प्लाट, खेती की जमीन की रजिस्ट्री अपनी बहन, पत्नी, बेटी के नाम से करा रहे हैं तो आपको दो फीसदी की छूट दी जा ही है। यह छूट रजिस्ट्री के लिए लगने वाले तीन प्रतिशत पंजीयन शुल्क में दी जा रही है।

30 जून के बाद लागू होगी नई कलेक्टर गाइडलाइन

पंजीयन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि 30 जून के बाद रजिस्ट्री में महिलाओं के नाम पर छूट मिलनी तो जारी रहेगी, लेकिन कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इसके चलते 20 फीसदी तक बढ़े हुए दाम पर रजिस्ट्री कराना पड़ सकता है। इससे रजिस्ट्री वर्तमान के बयाय महंगी हो जाएगी। इधर, प्रॉपर्टी से जुड़े लोगों मांग है कि इस बार भी कलेक्टर गाइडलाइन में जमीनों के दाम नहीं बढ़ाए जाने चाहिए।

महिलाओं के नाम पर छूट: महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर तीन की जगह एक फीसदी ही पंजीयन शुल्क लगेगा। इस तरह शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री 12.5 फीसदी की जगह 10.5 फीसदी पर होगी। इससे एक करोड़ रुपए की संपत्ति पर करीब दो लाख रुपए की बचत होगी। बता दें कि इस छूट की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में विश्व महिला दिवस के अवसर पर की थी।

75 की जगह 35 फीसदी ही देना होगा: अगर महिलाओं के नाम पर 30 साल से अधिक की लीज पर कोई जमीन, दुकान या मकान ले रहे हैं तो स्टांप शुल्क 75 की जगह 35 फीसदी ही देना होगा। यानी जहां पहले 75 हजार रुपये देने पड़ते थे, वहां महिलाओं के नाम पर लीज लेने पर 35 हजार रुपए ही देने होंगे। इस प्रावधान का फायदा लेने के लिए कई लोग संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए जो डीड पंजीयक वकीलों और सर्विस प्रोवाइडर से अपने नाम पर लिखवाई थी, अब उसे निरस्त कर फिर से पत्नी के नाम पर दस्तावेज बनवा रहे हैं। अभी 70 फीसदी रजिस्ट्री पुरुषों के नाम पर, जबकि 30 फीसदी महिलाओं के नाम पर होती हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की योजना बना रहा प्रशासन

नासिक छोड़ विदिशा की प्याज को पंसद कर रहे यूपी के लोग

800 हेक्टेयर में तीन लाख 20 हजार क्विंटल प्याज

संवाददाता, विदिशा

शरबती गेहूं के लिए प्रसिद्ध विदिशा जिला अब प्याज की पैदावार के लिए पहचान बनाने वाला है। जिले के किसान उन्नत बीजों के साथ नासिक की प्याज को मात दे रहे हैं। जिले में इस बार 800 हेक्टेयर में तीन लाख 20 हजार क्विंटल की पैदावार हुई है। इससे उत्साहित प्रशासन प्याज की राष्ट्रीय स्तर पर मार्केटिंग की योजना बना रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में प्याज की पैदावार के लिए मालवा क्षेत्र को जाना जाता है।

यहां के खंडवा, शाजापुर, रतलाम, इंदौर, उज्जैन जिलों में प्याज की खेती होती है, लेकिन विदिशा जिले में पिछले पांच साल में प्याज की खेती किसानों को भाने लगी है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्याज को एक जिला एक उत्पाद में शामिल कर लिया है जिसमें किसानों को खेती की सुविधा के साथ-साथ बाजार भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी।

किसानों को मिल रहे अच्छे भाव

जिले में भीमा गहरे लाल किस्म के प्याज की खेती होती है। इसकी खासियत होती है कि यह प्याज एक वर्ष तक खराब नहीं होता है। वहीं स्वाद भी अच्छा होता है। यही प्याज नासिक में भी होता है। नासिक से प्याज उत्तर प्रदेश जाता है, लेकिन अब विदिशा से भी भोपाल के व्यापारी प्याज उत्तर प्रदेश भेजने लगे हैं। इसमें परिवहन का खर्च बच रहा है। वहीं किसानों को भी अच्छे भाव मिल रहे हैं।

लागत से डेढ़ गुना ज्यादा मुनाफा

बरखेड़ा माखू ग्राम के किसान धनवीर सिंह चौहान ने बताया कि जिले में इस बार प्याज की बंपर पैदावार होने से किसान खुश हैं। उन्हें लागत से डेढ़ गुना ज्यादा मुनाफा हुआ है। इस बार एक हेक्टेयर में प्याज लगाई थी जिसमें 400 क्विंटल प्याज हुई है। उन्होंने गांव से ही 18 रुपए किलो प्याज बेच दी।

इनका कहना है

प्याज को राज्य सरकार की एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। इसके तहत जिले में प्याज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी शुरू कराई जा रही है, जिसमें प्याज का पेस्ट, सॉस, पावडर बनाएं जाएंगे। इसकी मार्केटिंग राष्ट्रीय स्तर पर कराई जाएगी। इससे किसानों को भी फायदा होगा।

डॉ. पंकज जैन, कलेक्टर, विदिशा

विदिशा जिले की जलवायु और मिट्टी प्याज की खेती के लिए अनुकूल है। बीते पांच सालों में प्याज का रकबा 400 हेक्टेयर से बढ़कर 800 हेक्टेयर हो गया है। आगामी वर्षों में यह रकबा दो हजार हेक्टेयर हो जाएगा। इस बार जिले में किसानों ने प्याज की बंपर पैदावार हासिल की है। देश में सबसे अधिक और अच्छा प्याज नासिक का माना जाता है, लेकिन अब गुणवत्ता के मामले में विदिशा का प्याज भी नासिक की बराबरी कर रहा है।

केएल व्यास, संयुक्त संचालक, उद्यानिकी विभाग

वैक्सीनेशन वारंटी ही नहीं, कोरोना से बचाव की गारंटी भी

मुकेश दुबे
जनसंपर्क अधिकारी, भोपाल

हम वो नासमझ हैं जो, कोरोना रूपी उबलते दूध से एक बार नहीं, दो बार जलने के बाद भी अपनी जिंदगी के प्रति गंभीर नहीं हैं। अब हमारी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ही वैक्सीनेशन को एक अभियान के रूप में चलाने जा रही है। क्योंकि यही सच भी है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव की वारंटी है। ये ऐसी वारंटी है, जो किसी भी रूप में किसी गारंटी से कम नहीं है।

कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंक कर पीता है, पर हम हैं कि मानते ही नहीं हैं। हम वो नासमझ हैं जो, कोरोना रूपी उबलते दूध से एक बार नहीं, दो बार जलने के बाद भी अपनी जिंदगी के प्रति गंभीर नहीं हैं। अब हमारी जिंदगी बचाने के लिए सरकार ही वैक्सीनेशन को एक अभियान के रूप में चलाने जा रही है। क्योंकि यही सच भी है कि वैक्सीनेशन ही कोरोना से बचाव की वारंटी है। ये ऐसी वारंटी है, जो किसी भी रूप में किसी गारंटी से कम नहीं है। सरकार द्वारा नि:शुल्क वैक्सीन की व्यवस्था के बाद हमारा यह कर्तव्य तो बनता ही है कि हम घर से निकलकर वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचें, टीका लगवाएं और दूसरों को भी वहां जाने के लिए प्रेरित करें। यह भी कि लोकतंत्र में जहां एक ओर सरकार की अपनी जिम्मेदारियां हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। कोरोना को समाप्त करने के लिए हमें निर्धारित कोरोना गाइड-लाइन का पालन करना चाहिए। वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। सभी को चाहिए कि वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना की समाप्ति तक कोरोना गाइड-लाइन को अपनी जीवन-शैली में शामिल करें। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की चौथी पारी जब शुरू की तो शपथ के बाद संभवत वो पहले मुख्यमंत्री होंगे, जो सीधे राजभवन से मंत्रालय जा पहुंचे। उनका पहुंचना जायज भी इसलिए था, क्योंकि देश-दुनिया के साथ मध्यप्रदेश भी इस अपरिचित, अनजानी कोरोना महामारी से बुरी तरह जकड़ा जा रहा था। डॉक्टर्स, वैज्ञानिक, प्रदेश के आला से लेकर हर अधिकारी इस बीमारी से लाड़ने के लिए अपने-अपने कयास लगा रहे थे। सब इस महामारी के छोर को पकड़ने की कोशिश में लगे थे। हर व्यक्ति अपने काम के मुताबिक कोरोना से लड़ने में लगा था। या यूं कहें कि कोरोना से लड़ने का, इस लड़ाई को जीतने का तरीका खोज रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता को कोरोना पर जीत का अपना तीन सूत्री मूलमंत्र बताया कि पहला सभी लोग घर पर रहें, दूसरा सिर्फ घर पर रहें, तीसरा सिर्फ घर पर ही रहें और जनता भी अपना सारा काम छोड़कर, अपने-अपने शहर छोड़कर वापस अपने घरों में समा गई। मुख्यमंत्री के सामने घर से बैठकर कोरोना से जंग लड़ते अपने कमजोर वर्ग के परिवारों की भोजन व्यवस्था करना भी एक चुनौती थी, जिसे उन्होंने कोरोना अवधि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने चुनिंदा अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ खाद्यान्न उपार्जन के साथ ही नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को सुनिश्चित किया। वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना से प्रदेश के उन मजदूरों को जो प्रदेश के बाहर रह रहे हैं, उन्हीं प्रदेशों में निःशुल्क खाद्यान उपलब्ध कराया। इस कोरोना ने वो सब कुछ दिखा दिया, जो हम सपने में भी नहीं सोचना चाहते। सिर्फ एक पॉजिटिव रिपोर्ट आने से एक सीमा के बाद न पिता काम आया, न पुत्र काम आया, न दौलत काम आई, न शोहरत काम आई, न धर्म काम आया न कर्म काम आया। न तुम काम आये और न ही हम काम आये। न रिश्ते काम आये और न ही रिश्तेदार काम आये। परंतु सच यह है कि काम आई तो सिर्फ सरकार, डॉक्टर, अस्पताल, सरकार के वॉलेंटियर्स, कोरोना वॉरियर, पुलिस और प्रशासन, जिन्होंने सिर्फ पेशेंट देखा और अपना काम। वरना सत्य यह भी था कि पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद घर के सामने अस्पताल की एम्बुलेंस और हाथ में दैनिक उपयोग की वस्तुओं का एक थैला और शून्य-सा भाव लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुआ पेशेंट। फिर न घर वाले मिलने आये और न ही रिश्तेदार। शायद वो भी गलत नहीं थे। बयार ही कुछ ऐसी थी कि वो जाते तो वो भी चपेट में आ जाते। ठीक होकर वापस घर आये तो ठीक, वरना अस्पताल में ही बिना रिश्तेदारों के अंतिम यात्रा की ओर उसी एम्बुलेंस में। यह सच्चाई याद दिलाना इसलिए भी अत्यंत जरूरी हो गया कि कोरोना की दूसरी लहर है तो अंतिम चरण में। पॉजिटिविटी दर भी 0.15 प्रतिशत तक आ गई। परंतु जरूरत इस बात की है कि आगे तीसरी लहर में पहले जैसी बदहवासी, अस्त-व्यस्तता नहीं होने पाए। उस स्थिति के आने के पहले ही तीसरी लहर को आने ही न दें और आ भी जाए तो कोई नुकसान नहीं होने पाये। इसलिए हर मोर्चे पर हर स्तर पर हमें कोरोना को समाप्त करना है। तीसरी लहर से लड़ाई के पहले जरूरी है कि हम कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लें। अब हमें इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि सरकार कहेगी तभी हम मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ बार-बार धोएँ, सेनेटाइजर का उपयोग करें, पानी खूब पिएं, योगा एवं व्यायाम को अपनी जिंदगी का साथी बना लें। ताजे फल, ताजा भोजन करें। यह वो छोटी-छोटी बातें हैं, जिनकी हम आदत डाल लें तो कोई परेशानी नहीं होगी। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने संदेश में कहा ही है कि कोरोना की तीसरी लहर से लड़ाई में वैक्सीनेशन ही हमारा मुख्य हथियार होगा। वैक्सीनेशन से किसी तरह का नुकसान नहीं है। कुछ लोग वैक्सीनेशन को गलत ठहरा रहे हैं। ये लोग न डॉक्टर हैं, न वैज्ञानिक और न ही सरकार के नुमाइंदे। फिर हम कोई नासमझ तो हैं नहीं कि कोरोना को इन्होंने ही देखा और भोगा है। हम सब इसके साक्षी हैं कि कोरोना एक ऐसी महामारी है, जिसके बारे में पहले कभी किसी को कोई अनुभव नहीं था। चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर्स ने अपने अनुभव और ट्रीटमेंट में प्राप्त परिणामों के आधार पर मरीजों का इलाज किया। फिर वैक्सीनेशन एक मोहल्ले या व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं रहा। इसे दुनिया के तमाम देशों में लोगों ने करवाया है। यही वजह है कि कई देशों में आज मास्क जरूरी नहीं है। सरकार ने वो सब किया, जिसकी हमें, आपको और देश-प्रदेश को जरूरत थी। अस्पतालों में बेड्स की व्यवस्था, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट, ऑक्सीजन, कंटेन्मेंट जोन बनाकर कोरोना को सीमित स्थान में ही किल करने जैसे प्रयास सरकार ने किए। फिर चाहें विदेशों से हो या अन्य प्रदेशों से ऑक्सीजन की उपलब्धता को निर्बाध रखने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफल प्रयास किए। सरकार को चिंता है तो सिर्फ जन-जीवन को बचाने की, मानवता को बचाने की। उसके लिए उन्होंने पूरे प्रयास भी किये। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर देश में कम्पलीट कोरोना कर्फ्यू की व्यवस्था हो अथवा राज्यों में राज्य सरकार द्वारा उसका पालन करवाने और घर में बैठी अपनी जनता का पालन-पोषण की व्यवस्था हो, सरकार ने हर मोर्चे पर सफलतापूर्वक काम किया। इसी का परिणाम है कि आज हम दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर को भी सुनियोजित ढंग से मात देने की तैयारी कर रहे हैं। परंतु यह भी सही है कि हमारा प्रयास यह हो कि हमें तीसरी लहर का सामना करने की जरूरत न पड़े।

जम्मू-कश्मीर में कारगर पहल: सरकार की कामयाबी का परिचायक

मोदी सरकार की दूसरी पारी में अगस्त 2019 को गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में यह कहकर देश सहित दुनिया को चौंका दिया था कि अनुच्छेद 370 और 35-ए को जम्मू-कश्मीर से हटाया जा रहा है और लद्दाख को अलग कर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह फैसला लेते समय यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही हालात सुधरेंगे, जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। यह चौंकाने वाला फैसला अवश्य था, लेकिन सच यह है कि 370 एक अस्थायी अनुच्छेद था। स्वतंत्रता उपरांत यह जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय के बाद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को संतुष्ट करने के लिए लाया गया था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू-कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले, उनसे इस राज्य ने एक विशिष्ट दर्जा हासिल किया। इसके तहत संसद द्वारा पारित कानून सीधे राज्य में लागू नहीं हो सकते थे। धीरे-धीरे इस विशिष्ट दर्जे ने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया और बाद में यह अलगाव और आतंक की जमीन तैयार करने का भी कारण बना। अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर की जनता और वहां के नेताओं का एक वर्ग खुद को भारत से अलग मानने लगा। इससे कश्मीर घाटी मुख्यधारा से लगातार कटती गई और वहां अलगाववादी जड़ें जमाने लगें। इन्हीं अलगाववादियों ने बाद में आतंकवाद की पैरवी शुरू कर दी। भाजपा अपने जनसंघ काल से ही अनुच्छेद 370 का विरोध करती आ रही थी, क्योंकि वह भेदभाव का जनक था और जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में लाने में बाधक था। इसे अन्य राजनीतिक दल भी समझ रहे थे, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से वे ऐसा कहने से बचते थे, जबकि भाजपा के हर घोषणा पत्र में यह उल्लेख होता था कि समय आने पर इस अनुच्छेद को हटाया जाएगा। आखिरकार यह समय 5 अगस्त 2019 को आया, जब इस अनुच्छेद को निरस्त किया गया, तब कांग्रेस सहित कई दलों ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। विश्व के कुछ देशों ने भी इस पर आपत्ति जताई, लेकिन मोदी सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही और उसे भारत का अंदरूनी मामला बताती रही। अंतत: विश्व को भी यह समझ आया कि यह वास्तव में भारत का आंतरिक मामला है। माना यह जा रहा था कि अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में अराजकता फैलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच तो यह है कि पिछले डेढ़ वर्ष में वहां हालात इतनी तेजी से बदले कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की भागीदारी वाले गुपकार गठबंधन को भी अपनी सोच बदलने के लिए विवश होना पड़ा। पिछले दिनों वे प्रधानमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जिस आतुरता से शामिल हुए, वह कश्मीर के बदले हुए माहौल का ही नतीजा है। इस सर्वदलीय बैठक में प्रमुख कश्मीरी नेताओं में से महबूबा मुफ्ती ने ही अनुच्छेद 370 की वापसी की मांग की, बाकी ने इस मसले को न उठाना ही बेहतर समझा। प्रधानमंत्री के आवास पर सर्वदलीय बैठक जैसे माहौल में हुई, वह मोदी सरकार की कामयाबी का परिचायक है। इस माहौल के लिए मोदी सरकार की ओर से जम्मू-कश्मीर में उठाए गए तमाम कदम जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो आतंकवाद पर लगाम लगाई गई और फिर माहौल ठीक देखकर जिला विकास परिषद के चुनाव कराए गए। इसके साथ ही वहां विकास के कई काम शुरू किए गए और वे अनेक फैसले लागू किए गए, जो अनुच्छेद 370 के कारण अमल में नहीं आ पा रहे थे।

इस्लामी जगत की हिंसा पर मौन

शंकर शरण,
राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार

हमास-इजराइल के बीच लड़ाई फिर शुरू होती दिख रही है, क्योंकि इजरायल की नई सरकार ने यह कहकर गाजा पट्टी पर बम बरसाए हैं कि हमास की ओर से उसके इलाके में आग लगाने वाले गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ इस्लामी जगत में इजरायल के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं, लेकिन यही आवाजें तब खामोश रहती हैं कि जब अफगानिस्तान में मार-काट मची होती है। इन दिनों अफगानिस्तान के हालात फिर बहुत खराब होते दिख रहे हैं। वास्तव में वहां ईद के बाद से ही हालात खराब होते जा रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो, जब बड़ी संख्या में निर्दोष-निहत्थे मुसलमान न मारे जाते हों। बीते दिनों तो पांच पोलियों कार्यकर्ताओं को भी मार डाला गया। पिछले महीने काबुल में एक स्कूल पर बमों से हमला कर 90 स्कूली लड़कियों और अन्य लोगों को मार डाला गया था, किंतु आश्चर्य है कि अफगानिस्तान का संहार दुनिया के मीडिया में कोई खास समाचार नहीं बनता। इसके विपरीत गाजा में एक मृतक मुस्लिम बच्ची का फुटेज, नाम सहित दुनिया भर के मीडिया में कई दिन चलते रहे। ऐसा विचित्र भैंगापन क्यों? क्या केवल इसलिए, क्योंकि अफगानिस्तान में सैकड़ों निर्दोष मुसलमानों की हत्याएं मुसलमानों ने ही कीं? क्या कारण है कि गाजा की मौतें तो चिंता का विषय बनती हैं, लेकिन अफगानिस्तान की नहीं-भले ही वहां बच्चे और महिलाएं ही क्यों न मारे जाएं? केवल अफगानिस्तान में ही बच्चे और महिलाएं हिंसा का शिकार नहीं बनते। ऐसा और देशों में भी होता है, जहां मुसलमान ही मुसलमान की हत्या करते हैं। कुछ वर्ष पहले पेशावर, पाकिस्तान में एक स्कूल में टाइम-बम लगाकर तहरीके-तालिबान ने सौ से अधिक स्कूली बच्चों और उनके अलावा अनेक शिक्षकों, कर्मचारियों को मार डाला था। वही हिसाब था। मृतक बच्चे मुसलमान थे। मारने वाले भी मुसलमान। मस्जिदों पर हमले कर सालाना असंख्य निर्दोष मुसलमानों को मार डालना पाकिस्तान में भी नियमित है। बलूचिस्तान के शिया नेता सैयद दाउद आगा के अनुसार, हम तो बस कब्र खोदने वाले समुदाय बन गए हैं। वे हमारी मस्जिदों के सामने आ-आकर मार डालो के आह्वान करते रहते हैं। इराक में भी कुछ वर्ष पहले इस्लामिक स्टेट ने एक कैदखाने पर हमला कर सभी शियाओं को चुन कर ट्रकों में भरा। उनकी संख्या 679 थी। उन्हें एक सुनसान स्थान ले जाकर गोली मार दी गई। यानी एक बार में लगभग सात सौ मुसलमानों को मार डाला गया। यहीं पर वे दृश्य भी याद करें, जब छोटे-छोटे अबोध मुस्लिम बच्चों को टाइम बम से लैस कर, महत्वपूर्ण जगहों पर रिमोट से आत्मघाती विस्फोट कराए गए। गत दो दशकों में ऐसा कई देशों में हुआ है। ऐसे कार्य सदैव जिहादियों ने ही किए हैं, परंतु ऐसे भयावह संहारों पर दुनिया में कभी कोई हाय-तौबा नहीं मचती कि बेचारे निर्दोष मुसलमान मारे गए। यूरोप, अमेरिका तो दूर, खुद मुस्लिम देशों में भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। न ही कभी मानवाधिकार उद्योग के प्रचारक उस पर सिर धुनते नजर आते हैं। सभी संवेदनशून्य बने रहते हैं।

मामला बिल्कुल साफ है कि मुस्लिम जमातें और नेता ही मुसलमानों की जान को अहमियत नहीं देते। यह स्थिति केवल कुछ कट्टरपंथियों की ही नहीं है। मुस्लिम देशों के शासक, कथित लिबरल मुस्लिम बौद्धिक, नेता आदि भी इस पर कुछ नहीं सोचते। कभी किसी को इन नियमित संहारों पर चिंता करते नहीं देखा सुना जाता, जो मुसलमानों द्वारा दूसरे मुसलमानों का होता है। ऐसी चुप्पी का मुख्य कारण है-इस्लामी मतवाद का बचाव करना। यदि लड़कियों के स्कूल, ब्यूटी पार्लर, अस्पताल आदि पर जिहादी हमलों का विश्लेषण होगा तो यह सामने आएगा कि वह सब इस्लाम के नाम पर ही किया जाता है। इस्लाम के अनुसार 11-12 वर्ष की आयु के बाद लड़की अकेले घर से बाहर नहीं निकल सकती। तब लड़की को परिवार के ऐसे पुरुष के साथ ही बाहर निकलना है, जिसके साथ शादी मना हो। जैसे पिता, सगा भाई आदि। यही कायदा शादीशुदा मुस्लिम स्त्रियों के लिए भी है। केवल उम्र-दराज स्त्रियों को इससे छूट है, जो बच्चे पैदा करने की आयु पार कर चुकी हों। इसीलिए तालिबान या इस्लामिक स्टेट लड़कियों के स्कूलों, कॉलेजों पर हमला करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से लड़कियों का ऐसे लड़कों के साथ होना इस्लाम विरुद्ध है, जिनसे उनकी शादी मना न हो। इसी कायदे से लड़कियों का स्कूल जाना, बाहर काम करना, मैत्री संबंध बनाना आदि वर्जित है। जो मुस्लिम लड़की, स्त्री अकेले घर से बाहर स्कूल, अस्पताल या ऑफिस जाने के लिए भी निकलती है, तो वह इस्लामी कायदों का उल्लंघन कर रही होती है। उन्हें दंडित करना इस्लामी नजरिये से जायज है। यही तालिबान या इस्लामिक स्टेट के दस्ते करते हैं।

» ईटीएच ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने विकसित की नई तकनीक

» धधकते सूरज के नीचे भी चौबीसों घंटे पानी इकट्ठा हो सकेगा

हवा की नमी से होगा जल संचय!

संवाददाता, भोपाल

भारत में बुंदेलखंड, विदर्भ, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान समेत कई इलाकों में किसान पानी को तरस रहे हैं। पानी की किल्लत सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि कई और देश भी इससे जूझ रहे हैं। इसलिए देश में नई-नई तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है। विज्ञान की तरक्की के साथ ही इंसान की तरक्की भी तय होती है। ऐसी ही हमारे वैज्ञानिकों ने हवा के नमी से जल संग्रहण की मिसाल पेश की है। गौरतलब है कि नॉर्थ अफ्रीका के देश मोरक्को में पानी की खेती होती है। यहां हवाओं की नमी को इकट्ठा करने वाली अनूठी तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों ने रेगिस्तान की भूमि को पानी से सींचने का काम कर दिखलाया है। इस अनूठी तरकीब से मोरक्को के पांच गांवों के 400 लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। इसी तरह पेरू में 1,20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पातीं। पेरू के एक शहर लीमा, जो रेगिस्तान में बसा हुआ है। जहां लगभग 20 लाख लोगों के सामने पानी की समस्या है। ये लोग भी कोहरा और ओस पकड़ने वाले जाल से पानी इकट्ठा कर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। मप्र मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक शैलेंद्र कुमार नायक के मुताबिक पहली बार, ईटीएच ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसी तकनीक विकसित की है जिससे बिना किसी ऊर्जा इनपुट के, यहां तक कि धधकते सूरज के नीचे भी चौबीसों घंटे पानी इकट्ठा हो सकता है।

सैद्धांतिक इष्टतम के निकट

नई तकनीक फॉयल पर आधारित सर्वोत्तम वर्तमान निष्क्रिय प्रौद्योगिकियों के रूप में प्रति दिन प्रति क्षेत्र कम से कम दोगुना पानी का उत्पादन कर सकती है। ज्यूरिख में एक ईटीएच भवन की छत पर वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में नए उपकरण के परीक्षण से पता चला। 10 सेंटीमीटर के फलक व्यास वाले छोटे पायलट सिस्टम ने वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में प्रति दिन 4.6 मिलीलीटर पानी दिया। बड़े पैन वाले बड़े उपकरण तदनुसार अधिक पानी का उत्पादन करेंगे। वैज्ञानिक यह दिखाने में सक्षम थे कि, आदर्श परिस्थितियों में, वे प्रति वर्ग मीटर फलक की सतह पर प्रति घंटे 0.53 डेसीलीटर पानी को हॉरवेस्ट कर सकते हैं। यह प्रति घंटे 0.6 डेसीलीटर (2.03 औंस) के सैद्धांतिक अधिकतम मूल्य के करीब है, जिसे पार करना भौतिक रूप से असंभव है।

लेपित ग्लास फलक

नए उपकरण में अनिवार्य रूप से एक विशेष रूप से लेपित ग्लास फलक होता है, जो दोनों और वातावरण के माध्यम से बाहरी अंतरिक्ष में अपनी गर्मी को भी विकिरणित करता है। सौर विकिरण को भी परावर्तित (रिफ्लेक्ट) करता है। इस प्रकार यह अपने आप को परिवेशी तापमान से 15 डिग्री सेल्सियस (59 डिग्री फारेनहाइट) तक ठंडा कर लेता है। इस फलक के नीचे, वायु से जल वाष्प संघनित होकर जल में परिवर्तित हो जाता है। प्रक्रिया वही है जो सर्दियों में खराब इंसुलेटेड खिड़कियों पर देखी जा सकती है।

यह विधि अपनाई

वैज्ञानिकों ने कांच को विशेष रूप से डिजाइन किए गए बहुलक और चांदी की परतों के साथ लेपित किया। बाहरी अंतरिक्ष के लिए,यह विशेष कोटिंग पहुंच फलक एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य खिड़की पर अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करता है। वायुमंडल द्वारा कोई अवशोषण नहीं है और न ही फलक पर रिफ्लेक्शन वापस आता है। डिवाइस का एक अन्य प्रमुख तत्व है, यह मुख्य रूप से वायुमंडल से ऊष्मा विकिरण को विक्षेपित करता है और आने वाले सौर विकिरण से फलक को कवच (शील्ड) देता है।

ऊर्जा की आवश्यकता

इवान हैचलर कहते हैं कि वह ईटीएच ज्यूरिख में थर्मोडायनामिक्स के प्रोफेसर डिमोस पौलिककोस के समूह में डॉक्टरेट के छात्र हैं। अन्य तकनीकों में आमतौर पर एक सतह से संघनित पानी को पोंछने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस कदम के बिना, संघनित पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सतह से चिपक जाएगा और आगे संघनन में बाधा डालते हुए अनुपयोगी रहेगा। ईटीएच ज्यूरिख शोधकर्ताओं ने एक नया सुपरहाइड्रोफोबिक (अत्यंत जल-विकर्षक) कोटिंग उनके पानी के कंडेंसर में फलक के नीचे की है। जिसके कारण यह संघनित पानी स्वयं ही गिर कर सग्रहित हो जाता है। हैचलर ने कहा इसका एक प्रमुख लाभ है। अन्य तकनीकों के विपरीत, यह वास्तव में बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के कार्य कर सकता है।

लाभादायक तकनीक

शोधकर्ताओं का लक्ष्य पानी की कमी वाले देशों के लिए एक तकनीक विकसित करना था और, विशेष रूप से, विकासशील और विकास के लिए उभरते देशों के लिए। अब, वे कहते हैं, जैसे पानी अलवणीकरण, उनकी उपज बढ़ाने के लिए अन्य वैज्ञानिकों के पास इस तकनीक को और विकसित करने या इसे अन्य विधियों के साथ संयोजित करने का अवसर है, लेपित पैन का उत्पादन अपेक्षाकृत सरल है और मौजूदा पायलट सिस्टम से बड़े पानी के कंडेंसर का निर्माण संभव है। जिस तरह से सौर सेलों में एक दूसरे के बगल में स्थापित कई मॉड्यूल होते हैं, उसी तरह कई पानी के कंडेंसर भी एक बड़े पैमाने पर सिस्टम को एक साथ जोड़कर रखा जा सकता है।

प्रदेश की पहली पंचायत, जिसने 100 फीसदी किया वैक्सीनेशन

» जबलपुर की बरेला नगर पंचायत के हर घर जाकर लिस्ट बनाई

» सात दिन में सबको डोज व बुजुर्ग-दिव्यांग को घर पर ही टीका

संवाददाता, जबलपुर

जबलपुर जिले की नगर पंचायत बरेला 100 फीसदी वैक्सीनेशन वाली प्रदेश की पहली नगर पंचायत बन गई है। सात दिन का विशेष अभियान चलाकर उसने यह टारगेट पूरा किया। नगर पंचायत ने शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को सौंप दिया है। यहां 18 प्लस वाले 10 हजार 299 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। बरेला नगर पंचायत के शत प्रतिशत निवासियों को कोरोना की वैक्सीन लगाने की रणनीति हफ्ते भर पहले बनाई गई थी। इस अभियान में 38 आंगनबाड़ी क्षेत्र के लिए टीमें बनाई गईं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, नगर परिषद के कर्मचारियों और राजस्व विभाग को मिलाकर टीम बनाई गई।

एक-एक व्यक्ति की पहचान

टीम ने सबसे पहले घर-घर जाकर ऐसे लोगों को सूची तैयार की, जिन्हें कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी थी। इसके बाद ऐसे सभी लोगों को पीले चावल देकर कोरोना की वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केंद्र आने का आमंत्रण दिया गया।

घर-घर पहुंचे विधायक

पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदू ने कार्यकर्ताओं के साथ खुद घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया और पीले चावल देकर टीकाकरण

केन्द्र आने के लिए आमंत्रित किया।

भ्रमित लोगों को समझाया

टीकाकरण को लेकर भ्रम में पड़े लोगों को समझाया और खुद का उदाहरण देते हुए बताया कि वे वैक्सीन लगा चुके हैं। दूसरी लहर में वैक्सीन लगवा चुके लोगों की मौत नहीं हुई। तब जाकर टीका न लगवाने की जिद कर रहे लोग वैक्सीन लगवाने तैयार हुए। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांगजन जो टीकाकरण केंद्र तक आने में असमर्थ थे, उन्हें घर-घर जाकर वैक्सीन लगाई गई।

मंत्री ने दी बधाई

शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन वाली पहली नगर पंचायत बनने पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने नगर पंचायत बरेला को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों को भी बरेला नगर पंचायत से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिले में अब तक 11 ग्राम पंचायतें भी 100 प्रतिशत वैक्सीनेट हो चुकी हैं।

सांसद ने सौंपा प्रमाण पत्र

बरेला को सौ फीसदी वेक्सीनेशन वाली नगर पंचायत घोषित करने आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद राकेश सिंह ने कहा कि प्रदेश की पहली नगर पंचायत का गौरव हासिल करने उपलब्धि पूरे जबलपुर जिले के लिए गौरव का विषय है। सांसद ने कहा कि विधायक सुशील तिवारी और यहां की टीम ने जिस तरह घर-घर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए प्रेरित किया, वह दूसरे के लिए प्रेरणादायक है।

सहयोग से भेदा लक्ष्य

बरेला नगर पंचायत कार्यालय में सांसद राकेश सिंह और पनागर विधायक सुशील तिवारी इंदू को मौजूदगी में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा को नगर पंचायत की ओर से शत-प्रतिशत वैक्सीनेशन का प्रमाण-पत्र सौंपा। विधायक इंदू तिवारी ने बरेला नगर पंचायत के लोगों और टीम को इसका श्रेय दिया। कहा कि उनकी विधानसभा क्षेत्र की बरेला नगर पंचायत के प्रदेश की पहली 100 प्रतिशत वैक्सीनेट नगर पंचायत बनने का गौरव हासिल करने पर वे अभिभूत हैं।

आम की खेती करने वाले किसानों को मिलेगा अनुदान

सब्सिडी पर आम की खेती के लिए आवेदन करें

संवाददाता, भोपाल

किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकारें लगातार प्रयास कर रही हैं, इसके लिए किसानों को व्यवसायिक फसलों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। औषधीय फसलों पर सरकार द्वारा पहले से ही किसानों को अनुदान दिए जा रहें हैं। अब मध्यप्रदेश सरकार एक नई योजना के तहत किसानों को आम की खेती करने वाले किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में फल क्षेत्र विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इसके लिए किसानों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं।

फल क्षेत्र विस्तार (राज्य) योजना

राज्य में बागवानी के विस्तार के लिए सरकार ने आम की फसल के लिए प्रोत्साहन दे रही है। यह योजना आम की तोतापरी किस्म को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही है। योजना के तहत किसानों को तोतापरी किस्म की उच्च घनत्व पर बागवानी पर अनुदान दिया जाएगा।

तीन जिलों के लिए योजना

यह योजना मध्य प्रदेश के तीन जिलों के किसानों से आनलाइन आवेदन मांगा गया है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, हरदा और बैतूल जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए राज्य उधानकी विभाग ने लक्ष्य जारी किए है। इस बार आम की बागवानी के लिए 148 एकड़ के लिए 63.94 लाख रूपये का लक्ष्य रखा है। जिले के अनुसार सामान्य, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग-अलग लक्ष्य तय किए गए हैं।

1. **होशंगाबाद:** जिले में आम की बागवानी के लिए लिए कुल 59 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 25.49 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 39 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 10 एकड़ का लक्ष्य रखा है।
2. **हरदा:** जिले में आम की बागवानी के लिए कुल 35 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 15.12 लाख रुपए की सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 20 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 10 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।
3. **बैतूल:** जिले में आम की खेती के लिए 54 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 23.33 लाख रुपए का सब्सिडी दिया जा रहा है। योजना के तहत सामान्य वर्ग के लिए 35 एकड़, अनुसूचित जाति के लिए 4 एकड़, अनुसूचित जनजाति के लिए 15 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है।

मुनाफा कमाने बीज विक्रेता किसानों पर थोप रहे अमानक बीज

भोपाल। बीज विक्रेता अधिक मुनाफा कमाने के फेर में किसानों को उन्नत किस्म के नाम पर स्थानीय स्तर पर पैक किया गया सामान्य व अमानक बीज बेच रहे हैं। इसके अलावा बीज विक्रेताओं की दुकान से छत्तीसगढ़ व उत्तरप्रदेश के कई ऐसी ब्रांड के नाम पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका पहले नाम ही नहीं सुना गया है। भोले-भाले किसानों को उन्नत किस्म का नया बीज बताकर उनसे मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। प्रदेश के कई जिलों के ग्रामीण अंचल तक की दुकानों पर यह मनमानी चल रही है। इन सबके बावजूद कृषि अधिकारी जांच से कन्नी काट रहे हैं। किसानों के साथ हो रही ठगी पर लगाम लग सके। इसके लिए कृषि अधिकारियों को युद्ध स्तर पर एक साथ कई टीमों का गठन कर जांच अभियान चलाना होगा।

बाजार में कई नए ब्रांड के बीज उपलब्ध

विभागीय अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया तो जांच व सेंपलिंग की कवायद केवल खानापूर्ति तक सीमित होकर रह जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में बीज, खाद व कीटनाशकों की जांच के लिए कृषि विभाग का दल सक्रिय है। जाहिर है कि इन दो दलों द्वारा पूरे जिले में जांच करना संभव नहीं है।

किसान लाभ लेने के लिए करें आवेदन

सिंचाई यंत्रों पर राज्य सरकार दे रही सब्सिडी

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। कृषि में उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई यंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसको ध्यान में रखकर सरकार किसानों को सिंचाई यंत्रों पर अनुदान देकर प्रोत्साहन भी दे रही है। जिससे सभी किसान इनका उपयोग कर फसल उत्पादन बढ़ा सकें। किसानों को सिंचाई यंत्रों (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प सेट) पर अनुदान देने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। चयन हो जाने पर किसानों को इन यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जाती है। अभी मध्यप्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा नेशनल फूड सिक्यूरिटी मिशन एवं बुंदेलखंड विशेष पैकेज के तहत किसानों से आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक किसान आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

किसान कर सकते हैं आवेदन

बुंदेलखंड विशेष पैकेज योजना-दलहन के अंतर्गत छह जिलों (सागर, दमोह, पन्ना छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी) में सिंचाई उपकरण (पाइपलाइन, स्प्रिंकलर, विद्युत पम्प सेट) के तहत आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन एवं ऑइल पाम) के अंतर्गत सभी जिलों में (पाइपलाइन सेट, स्प्रिंकलर सेट, विद्युत पम्प सेट) एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (धान) के अंतर्गत 8 जिलों (कटनी , मंडला , डिंडोरी , दमोह , पन्ना , रीवा , सीधी, अनूपपुर) में (पाइपलाइन सेट , विद्युत पम्प सेट) के लिए किसान आवेदन कर सकते हैं।

इन यंत्र पर मिलेगी सब्सिडी स्प्रिंकलर सेट, पाइप लाइन सेट, विधुत पम्प सेट

दी जाने वाली सब्सिडी

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन वर्ष 2020-21- इस योजना के तहत किसानों को पाइप लाइन सेट 50 प्रतिशत अनुदान पर, पम्प सेट पर 50 प्रतिशत का अनुदान, स्प्रिंकलर सेट पर लघु/सीमांत कृषक, समस्त वर्ग के लघु/सीमांत कृषकों के लिए इकाई लागत का 55 प्रतिशत अनुदान देय हैं। अन्य कृषक, समस्त वर्ग के अन्य कृषकों के लिए इकाई लागत का 45 प्रतिशत अनुदान देय हैं। इसके अतिरिक्त किसान पोर्टल पर उपलब्ध सब्सिडी कैलकुलेटर पर भी दी जाने वाली सब्सिडी एवं कृषक अंश की जानकारी भी देख सकते हैं।

4 जुलाई तक कर करें आवेदन

राज्य के किसान योजना के तहत जारी जिलेवार लक्ष्यों के तहत दिनांक 22 जून 2021 दोपहर 12 बजे से 04 जुलाई 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरूद्ध लॉटरी दिनांक 05 जुलाई 2021 को सम्पादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची शाम 5 बजे पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। चयनित किसान सिंचाई उपकरण अनुदान पर ले सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज

1. आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के प्रथम प्रष्ठ की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषकों के लिए।
2. बिजली कनेक्शन का प्रमाण जैसे बिल सिंचाई यंत्र।

सब्सिडी पाने यहां करें आवेदन

मप्र के किसान दिए गए सिंचाई यंत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर कर सकते हैं। किसान मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान कहीं से भी अपने मोबाइल अथवा कंप्यूटर के माध्यम से आवेदन भर सकेंगे। आवेदन अंतर्गत भरे गए मोबाइल नंबर पर कृषकों को एक ओटीपी प्राप्त होगा। इसके माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पंजीकृत हो सकेंगे। पोर्टल अंतर्गत आगे सम्पादित होने वाली सभी प्रक्रियाओं में भी बायोमेट्रिक के स्थान पर व्यवस्था लागू होगी।

खरीफ के सीजन में अधिक पैदावार के लिए करें बोवनी

मक्का की नई उन्नत किस्में किसानों करे देंगी मालामाल

संवाददाता, भोपाल

मक्का की खेती का नम्बर देश में धान तथा गेहूं के बाद तीसरे नंबर पर आता है। इसकी खेती वर्ष में दो बार होने के कारण उत्पादन काफी अधिक होता है। मक्के के अधिक उत्पादन के लिए यह जरुरी रहता है की मक्के का बीज तथा बोवनी का सही समय होना चाहिए। खरीफ मक्के की बोवनी के लिए जून का महीना उचित माना जाता है। इसके बाद की गई मक्के की बोवनी में कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। रबी मक्का अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से 15 नवंबर तक और जायद मक्का के लिए मार्च के प्रथम पखवाड़ा में बोने के लिए उपयुक्त है। किसानों को अधिक उत्पादन एवं आय के लिए मक्का की उन्नत किस्मों की खेती करना चाहिए। उन्नत किस्मों की खेती से न केवल अधिक उत्पादन होता है, बल्कि कीट-रोग प्रतिरोधी होने के कारण लागत में भी कमी आती है। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा अलग-अलग जलवायु क्षेत्रों के अनुसार मक्का की कई किस्में विकसित की गई हैं, जिनकी जानकारी **'जागत गांव हमार'** किसानों के लिए लेकर आया है।

बोवनी के लिए बीज दर

मक्के की बोवनी सीडड्रिल से करना चाहिए जिससे मक्का एक कतार में रहता है। इससे मक्के की निराई और खरपतवार निकासी करने में आसानी होती है। 8-10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज के लिए उपयुक्त होता है। बोवनी में पौधे से पौधे की दूरी 20 सेमी व पंक्ति से पंक्ति की दुरी 60-10 सेमी रखनी चाहिए।

अच्छी उपज के लिए खाद

खरीफ मक्का की 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पैदावार लेने के लिए 150 किलोग्राम नाईट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की जरूरत होती है। स्फुर तथा पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाईट्रोजन का 10-15 प्रतिशत बोनी के समय दें। बची हुई नाईट्रोजन का 25, 45 व 60 दिनों के बाद उपयुक्त मात्रा का छिड़काव करें।

खरपतवार प्रबंधन

खरीफ मक्का की कम पैदावार का सबसे प्रमुख कारण खरपतवार है। मक्का के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक भारत में बहुत कम उपलब्ध हैं। इस मौसम में मुख्य खरपतवार मोथ तथा कुछ चौड़ी व संकरी पत्ती के खरपतवार हैं।

खरपतवार नियंत्रण के लिए विधियां

स्टेल सीड बड़े तकनीक: इस विधि में फसल बोने से पहले खरपतवारों को उगाया जाता है। बाद में ग्लाइफोसेट 15 मिली/ लीटर पानी तथा 2-4 डी 2 मिली/लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जाता है। स्टेल सीड बड़े तकनीक में सामन्य तौर पर मई में खेत में मेड़ बनाकर छोड़ दी जाती है, जिससे कि पूर्व मानसून वर्षा से खरपतवार उग जाएं। इसके बाद खेत को बिना जोते ही मक्का की बोवनी कर दी जाए। इस विधि का प्रयोग करने से खरपतवारों की संख्या कफी हद तक कम हो जाती है।

अजय: मेड़ के ऊपर मक्का की बोवनी करने के दो-तीन दिन के अंदर पेंडीमेथिलिन + एट्राजीन (1 लीटर + 600 ग्राम) प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करने पर खरपतवारों का जमाव कम होता है। बोवनी के 20 से 30 दिनों बाद एट्राजीन + 2, 4 डी. (600 + 400 ग्राम/एकड़) का छिड़काव करने से खरपतवारों का कफी हद तक नियंत्रण हो जाता है।

रोग और कीट प्रबंधन

खरीफ मक्का की शुरुआती अवस्था में पत्तीछेदक कीट आते हैं। इनको क्लोरोपायरिफास और सायपरेंथेलिन 2 मिली/लीटर पानी में मिलाकर छिड़कने से कीटों के आक्रमण को रोका जा सकता है। तनाछेदक कीट के नियंत्रण के लिए फ्यूराडान 30 से 50 दिनों के मक्का में एक-एक चुटकी गाभा में डालने से इसका प्रकोप कम होता है। तनाछेदक कीट का प्रकोप अधिक होने पर फ्लूबेंडीअमाइड (फेम) 75 मिली/हेक्टेयर या कलोरएंट्रानिलप्रोल 75 मिली/ हेक्टेयर या एमिना मेक्टिनबेन्जोयेड 12.5 मिली/हेक्टेयर का प्रयोग करें।

मक्का की उन्नत किस्में व पैदावार

यह वर्ष में दो बार किए जाने वाली फसल है। दोनों मौसम में बीज की प्रजातियां अलग-अलग होती हैं। इसके साथ ही उत्पादन भी। नीचे दी हुई सभी प्रजाति खरीफ मौसम की हैं।

एचक्यूपीएम: मक्का की यह किस्म 88 से 90 दिन में तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन 60 से 65 क्विंटल प्रति हंक्टेयर है। इस प्रजाति के मक्के के बीज का रंग हल्का होता है।

एचक्यूपीएम-5: मक्के की यह प्रजाति उच्च उत्पादन के लिए जाना जाता है। 90 दिनों में तैयार होने वाली मक्के का उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रजाति के मक्के के बीज का रंग हल्का पीला होता है।

एचएम-5: मक्के की इस प्रजाति के बीज का रंग सफेद होता है। यह 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन क्षमता 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है।

केएमएच-3426: मक्के की यह प्रजाति 90 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाता है। इसका उत्पादन क्षमता 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रजाति के मक्के के बीज का रंग हल्का पीला होता है।

विवेकक्यूपीएम-9: मक्का की यह किस्म सबसे कम दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रजाति के मक्के के बीज का रंग पीला होता है।

डीएचएम-11: मक्के की यह प्रजाति सबसे ज्यादा दिनों में तैयार होने वाली है। यह किस्म 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इसका उत्पादन 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इस प्रजाति के मक्के का बीज हल्का पीला होता है।

पालीहाउस, शेड नेट हाउस, प्लास्टिक मल्चिंग, ग्रीन हॉउस एवं फूलों की खेती पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें

सरंक्षित खेती योजनाः 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देगी सरकार

संवाददाता, भोपाल

किसानों को नुकसान से बचाने के लिए सरकार तरह तरह के प्रयास कर रही है। इन परिस्थितयों को देखते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें सरंक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत सरकार किसानों को पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फलों और फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदान दे रही है। संरक्षित खेती के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों को सम्मिलित किया गया है। इन घटकों के तहत अलग-अलग लक्ष्य जारी कर किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन सभी योजनाओं पर किसानों को सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य के किसान सब्सिडी पर खेती के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं।

किसानों को मिलने वाला लाभ

मध्य प्रदेश के किसान संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। किसान इन सभी में से किसी एक योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सभी वर्गों के लिए योजना

राज्य में सभी वर्ग के किसानों को सरंक्षित खेती योजना के तहत पाली हाउस खेती, प्लास्टिक मल्चिंग, शेड-नेट हाउस, ग्रीन हाउस एवं फूल-फलों की खेती आदि घटकों पर लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है।

शेड नेट हॉउस/ट्यूब्लर स्ट्रक्चर

उच्च कोटि की सब्जियों की खेती: पाली हॉउस/ शेडनेट हॉउस

प्लास्टिक मल्चिंग

ग्रीन हॉउस ढांचा (ट्यूब्लर स्ट्रक्चर): 2080 से 4000 वर्गमीटर तक

क्राईसंथेमम, गुलाब और लिली की खेती: पाली हाउस / शेडनेट हॉउस

13 जिलों के किसान कर सकते हैं आवेदन

मध्य प्रदेश में संरक्षित खेती योजना के तहत विभिन्न प्रकार के घटकों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत राज्य के 13 जिलों के किसानों से आवेदन कर सकते हैं। यह जिले इस प्रकार है :- खरगोन, रतलाम, गुना, ग्वालियर, देवास, बलाघाट, धार, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर, अनुपपुर, कटनी।

पीएम की मन की बात में सतना का देशी म्यूजियम

» सतना के रामलोटन कुशवाह ने अपने खेत में देशी म्यूजिम बनाया है और इसमें अलग-अलग तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं...

संवाददाता, भोपाल/सतना

मध्य प्रदेश के सतना के रामलोटन कुशवाह ने अपने खेत में देशी म्यूजिम बनाया है। इसमें अलग-अलग तरह के औषधीय पौधे लगाए गए हैं। 250 से ज्यादा औषधीय पौधों का संग्रहण राम लोटन ने किया है जिसकी तारीफ रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में की। प्रधानमंत्री द्वारा रेडियो के माध्यम से मन की बात के द्वारा देशभर के लोगों को नई और रोचक जानकारियां भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही ऐसे लोगों की प्रशंसा भी की जा रही है जो कुछ नया करते हैं। गौरतलब है कि '**जागत गांव हमार**' ने अपने पिछले अंक में 'राम' की बगिया में संजीवनी शीर्षक से प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मप्र के सतना जिले के किसान रामलोटन कुशवाह के देशी म्यूजियम की जमकर सराहना की। पीएम

मोदी ने कहा कि रामलोटन कुशवाह ने अपने खेत में एक देशी म्यूजियम बनाया है। वहां रामलोटन सैकड़ों औषधीय पौधों और बीजों का संग्रह किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे शास्त्रों में नास्ति मूलम् अनौषधम्, अर्थात पृथ्वी पर ऐसी कोई वनस्पति ही नहीं है, जिसमें कोई न कोई औषधीय गुण न हो।

जागत गांव हमार की खबर पर मुहर

राज्य मंत्री ने भी सुनी सराहना: रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना जिले के सम्मानित किसानों के नेतृत्व में दुर्लभ जड़ी बूटियों का संरक्षण करने वाले पिथौराबाद नई बस्ती के रामलोटन कुशवाहा की प्रसंसा की। सुबह 11 बजे से हुए इस कार्यक्रम को रेडियो में सतना के अमरपाटन से विधायक व राज्यमंत्री रामखेलावन पटेल सहित अन्य ने भी सुना।

म्यूजियम खास

किसान राम लोटन सब्जियों के देसी बीज और जड़ी-बूटी के संरक्षण में जुटे हैं उनकी बगिया में इस वक्त 250 से ज्यादा औषधीय पौधे हैं। पक्के मकान की एक दीवार पर लटकी कई आकार की सूखी लौकियां और सब्जियों की फलियां अक्सर यहां आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। इस मकान और इसके आसपास ऐसा बहुत कुछ और भी है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लाता है।

अपनी दीवानगी बताते हैं रामलोटन कुशवाह

राम लोटन का कहना है कि देसी सब्जियों और जड़ी-बूटियों से मुझे इतना स्नेह है कि दिन-रात कब ढल जाते हैं, इसका पता नहीं लग पाता। आप ये मान लीजिए यही सब्जियां और जड़ी बूटियां मेरा सब कुछ हैं। राम लोटन कुशवाहा, देशी सब्जियों और जड़ी बूटियों के संरक्षण के प्रति अपनी दीवानगी बताते हैं। 64 वर्ष के रामलोटन सतना जिले के उचेहरा ब्लॉक के गांव अतरवेदिया के निवासी हैं। उनका गांव जिला मुख्यालय सतना से 25 किलोमीटर दूर है। यहीं पर रामलोटन एक एकड़ कुछ कम खेत में औषधीय गुणों से भरी जड़ी बूटियों का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। साथ में हर साल कई तरह की सब्जियां उगाते हैं।

» असम, बिहार, मुंबई, कर्नाटक व पंजाब से इंजीनियरों की टीम पहुंची हरदा

» टीम में फिजिकल सर्वे के लिए सलाहकार, आर्किटेक्ट, कृषि विश्लेषक भी

» किसानों को दी जाने वाली सुविधा, भुगतान व्यवस्था की जानकारी हासिल की

हाईटेक होगी हरदा की कृषि मंडी

संवाददाता, हरदा

करीब एक दशक पहले प्रदेश में आदर्श कृषि उपज मंडी का दर्जा हासिल कर चुकी हरदा की मंडी जल्द ही मप्र में हाईटेक मंडियों की फेहरिस्त में शुमार हो जाएगी। इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। इस मंडी को प्रदेश में पायलेट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है।

इसे हाईटेक बनाने के लिए अधोसंरचना, खरीदी, भुगतान व अन्य किन-किन सुविधाओं की दरकार है। इसकी ग्राउंड रियलिटी जांचने देश के विभिन्न 5 राज्यों की टीम मंडी के दो दिनी दौरे पर आई है। असम, बिहार, मुंबई, कर्नाटक व पंजाब से आई इंजीनियरों की टीम हरदा पहुंची। इस टीम में इंजीनियरों के अलावा, फिजिकल सर्वे के लिए सलाहकार, आर्किटेक्ट, कृषि विश्लेषक भी आए हैं। टीम ने सुबह और दोपहर में मंडी परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया।

39 मंडियां होंगी हाईटेक

टीम ने मौजूदा संसाधन, शेड, खरीदी की प्रक्रिया, गुणवत्ता की परख के इंतजाम, किसानों को दी जाने वाली सुविधा, भुगतान व्यवस्था, पेयजल, तौल व्यवस्था की जानकारी हासिल की। मप्र में 39 मंडियों को मंडी बोर्ड द्वारा हाईटेक किया जाना प्रस्तावित है। इसमें हरदा मंडी का नाम भी शामिल है। खास बात यह है कि इसे पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लिया है। इसी कारण यहां सबसे पहले 5 प्रदेशों की सर्वे टीम भेजी गई है।

मंडी बोर्ड को देंगे रिपोर्ट

टीम द्वारा मौजूदा स्थिति का आंकलन करने के बाद और किन सुविधाओं की दरकार है, उसकी रिपोर्ट बनाकर मंडी बोर्ड को सौंपी जाएगी। जिससे यहां जरूरत के अनुसार बैंकिंग भुगतान, खरीदी के शेड, विश्राम स्थल, खाद, बीज, कृषि मशीनरी आदि की सुविधा दी जा सके।

इन बिंदुओं पर की पड़ताल

टीम ने दिन में सर्वे व निरीक्षण के बाद दोपहर में मंडी में उपज बेचने आए किसानों से भी जानकारी ली। बातचीत के दौरान टीम ने किसानों से पूछा कि यहां कौन सी मुख्य फसल होती हैं। वे किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। इसका क्या आधार होता है। कौन सी फसल पूरे क्षेत्र के लिए आर्थिक ढांचे को मजबूती देने का काम करती है।

सुविधाओं पर फोकस

वे पहले कौन से फसल ज्यादा बोते थे, बीते सालों में क्यों और क्या बदलाव किए हैं। वहीं लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी चर्चा की। व्यापारियों से खरीदी में आने वाली परेशानी व अपेक्षित सुविधाओं के बारे में ब्यौरा लिया, जिससे भविष्य में मंडी हाईटेक बनाई जा सके। मंडी के कार्यालय अधीक्षक आरके पारे ने बताया कि टीम दो दिन रुकी। मंडी को हाईटेक बनाने के लिए सर्वे चल रहा है।

20 मॉडल विकासखंडों से दो लाख किसान परिवार होंगे लाभान्वित

नव-नियुक्त अधिकारियों को राज्य मंत्री कुशवाह ने पढ़ाया पाठ

संवाददाता, भोपाल

उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि प्रदेश में उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 मॉडल विकासखंडों को विकसित किया जाएगा। इनके माध्यम से उद्यानिकी फसलों के उत्पादन से जुड़े दो लाख किसान परिवार लाभान्वित होंगे। विभाग में सहायक उद्यानिकी विस्तार अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। राज्य मंत्री गुलाब उद्यान में वर्ष 2017 बैच के नव-नियुक्त अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि विभाग

की योजनाओं को नव-नियुक्त अधिकारी अच्छी तरह से समझें। किसानों को योजनाओं की जानकारी से अवगत कराएं। अच्छा कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। योजनाओं में लक्ष्यों का निर्धारण किसानों की मांग के अनुसार किया जाए।

सरकार किसानों से बातचीत हो हर समय तैयारः तोमर

संवाददाता, भोपाल

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाया गया है। ये कानून देशभर के किसानों के लिए बना है। किसानों को जिस प्रावधान में दिक्कत है, उसे बताएं, सरकार उस पर विचार कर सकती है। तोमर प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से चर्चा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि किसान यूनियन के नेताओं के साथ 10-11 बार बात हो चुकी है। 50 घंटे से अधिक चर्चा हो चुकी है। उनकी परेशानियां समझने की कोशिश की है। भारत सरकार

किसानों को जिस प्रावधान से दिक्कत है, उसे बताएं

आज भी पूरे मन से कह रही है कि किसान को जिस प्रावधान से दिक्कत हो, वह खुले मन से बताएं। हम विचार और निराकरण के लिए तैयार हैं।

आगे भी जब भी किसानों की बातचीत का प्रस्ताव आएगा तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि धारा 370 की समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में पूरी तरह शांति और सौहार्द्र का वातावरण है। वहां पंचायत चुनाव हो चुके हैं और पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने वहां के विकास के लिए बड़ी राशि दी है।

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
राहतगढ़, भगवान सिंह प्रजापति-9826948627
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पताः- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)